

विकासकार्य पर बकाया ऋण

*869. श्री जगन्नाथराव जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन-पूर्व ऋण की कितनी राशि पाकिस्तान पर बकाया है तथा यह कब से बकाया है;

(ख) उस पर कितना ब्याज चढ़ गया है तथा उसमें विदेशी मुद्रा का भ्रज कितना है, और

(ग) पाकिस्तान में उक्त बकाया राशि पाने के लिये शिमला करार करने समय और दिल्ली वार्ता के दौरान हुई चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं तथा समस्याओं को मुलमलाने की भावना से पाकिस्तान ने क्या क्या बचन दिये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० झार० गणेश) : (क) भारत का पाकिस्तान पर विभाजन ऋण का लगभग 300 करोड़ रुपया बकाया है; ऋण की सही रकम के बारे में सहमति नहीं हो सकी है। विभाजन की व्यवस्था के अनुसार पाकिस्तान द्वारा 15 अगस्त, 1952 में इस ऋण की मूल रकम व ब्याज की रकम (2 7/8 प्रतिशत वार्षिक) दोनों बराबर-बराबर की 50 किस्तों में वापस की जानी थी।

(ख) चूंकि वहां की सरकार ने अभी तक कोई किरत नहीं दी है, इसलिए पाकिस्तान द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की रकम मूल ऋण व ब्याज के लौटने तक बढ़ती जायेगी। यह मारा ऋण भारतीय रुपयों में वापस किया जाना है।

(ग) जुलाई, [1972 में शिमला में शिखर वार्ता में भारत और पाकिस्तान

के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया था। अभी हाल में नयी दिल्ली में भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच जो द्विपक्षीय बात-चीत हुई थी वह मुख्यतः अपने-अपने देशों को वापस भेजे जाने वाले व्यक्तियों के तीन-तर्फा कार्यक्रम और 196 युद्ध बन्धियों के प्रश्न के बारे में श्री विभाजन ऋण के प्रश्न पर पाकिस्तान के साथ दुबारा वार्ता-चीत जारी नहीं की जा सकी है।

Industrial projects with Soviet assistance

*870. SHRI N. SHIVAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether investments in new Industrial projects with Soviet assistance are not envisaged in 1974; and

(b) if so, the reasons therefor

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) Investments in Industrial Projects with Soviet assistance are envisaged during 1974. While the major part of Soviet assistance as of now will be in respect of continuing schemes, the possibility of new schemes also being taken up cannot be ruled out. However, full details of all such projects would be known only after sometime, after discussion with the Soviet authorities and other preliminary action such as preparation of feasibility reports, detailed project report, negotiations regarding supplies of specific items and conclusion of relevant contracts.

(b) Does not arise.

Amount sanctioned for Development of tourist spots in West Bengal

*871. SHRI A. K. M. ISHAQUE: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state: